प्रदेश को औषधीय कृषि हब के रूप में विकसित करने की तैयारी

अमर उजाला ब्यूरो

कृषक उत्पादक समूहों को केंद्र में रखकर बनेगी कार्ययोजना

एनएमपीबी को भेजे जाएंगे 83 समूहों के प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश को औषधीय कृषि हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड (एनएमपीबी) का सहयोग लिया जाएगा। शासन ने निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड को भेजने का निर्देश दिया है।

प्रदेश में कई कृषक उत्पादक समूह (एफपीओ) काफी समय से औषधीय खेती कर रहे हैं। कोविड काल में एफपीओ द्वारा उत्पादित औषधियों की मांग अचानक बढ़ गई थी। 39 कृषक उत्पादक समूहों ने औषधीय व सगंध खेती के जरिए अच्छा लाभ कमाया था। इतना ही नहीं दूसरे कृषक उत्पादक समूह भी औषधीय खेती की ओर आकर्षित हुए। लेकिन इन्हें शासन स्तर पर सक्रिय मार्गदर्शन व सहयोग मिलने में मुश्किल आ रही थी। इसको देखते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने प्रदेश में कृषक उत्पादक समूहों को औषधीय व सगंध खेती में सहायता संबंधी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 83 कृषक उत्पादक समूहों का माइक्रो एक्शन प्लान तैयार करवाया जा रहा है। स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड (एसएमपीबी) कार्ययोजना तैयार कर एनएमपीबी को भेजेगा। निदेशक राज्य कृषि प्रबंध संस्थान रहमानखेड़ा एसएमपीबी के भी नोडल अधिकारी हैं। एनएमपीबी की संस्तुति पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय आवश्यक वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराता है। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में 700 से अधिक एफपीओ कार्यरत हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर 2000 तक की जानी है। इससे पूरे प्रदेश में औषधीय खेती को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी।